पाक-अधिकृत कश्मीर में जून 2026 के प्रदर्शन: आरक्षित शरणार्थी सीटें, JAAC प्रतिबंध और तीन-चरणीय चुनाव

समाचार-संदर्भ: जून 2026 (प्रदर्शन और JAAC प्रतिबंध) | प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026

भारत-पाकिस्तान, कश्मीर प्रश्न और क्षेत्रीय राजनीति | समाचार संदर्भ: जून 2026 (प्रदर्शन और प्रतिबंध); बाद की स्थिति अक्टूबर 2026 तक | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

जून 2026 में पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में वर्षों का सबसे बड़ा नागरिक संघर्ष भड़का। 5 जून को क्षेत्रीय प्रशासन ने **जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC)** को आतंक-विरोधी कानून (AJK Anti-Terrorism Act, 2014) के तहत **प्रतिबंधित** कर दिया; 8 जून को रावलकोट में हिंसक झड़पों में **11 लोग मारे गए** (Al Jazeera, 9 जून 2026)। विवाद के केंद्र में थी विधानसभा की **12 आरक्षित 'शरणार्थी सीटों'** की माँग — कि ये सीटें वास्तव में PoK में रहने वालों को मिलें।

खबरों में क्यों

मई 2026 के अंत में सरकार और JAAC के बीच वार्ता टूट गई; 27 जुलाई को क्षेत्रीय चुनाव तय थे। JAAC ने 9 जून को मुज़फ़्फ़राबाद की ओर मार्च और हड़ताल का आह्वान किया — उसी दिन चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू होने थे (The Hindu, 13 जून 2026)। प्रतिबंध, इंटरनेट बंदी और गिरफ़्तारियों के बावजूद हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे; BBC के अनुसार 11 जून तक कम से कम 15 मौतें हो चुकी थीं और 10,000 से अधिक लोगों का जत्था रावलकोट के बाहर था।

मूल विवाद: 12 आरक्षित सीटें क्या हैं?

विधानसभा की संरचना: PoK की विधानसभा में कुल **53 सीटें** हैं — 45 निर्वाचित (33 सामान्य + 12 शरणार्थियों के लिए आरक्षित) और 8 नामांकित (5 महिला, 1 तकनीशियन, 1 धर्म-विद्वान, 1 प्रवासी) (The Hindu, 13 जून 2026)। 12 सीटें उन समुदायों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर के भारत-प्रशासित हिस्से से पाकिस्तान आकर बस गए; इन सीटों के मतदाता पाकिस्तान में बसे शरणार्थी समुदाय हैं, PoK के निवासी नहीं।

मत-भार का असंतुलन: पत्रकार लव पुरी के विश्लेषण के अनुसार 12 शरणार्थी सीटों में लगभग **4.36 लाख** पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि PoK की 33 सामान्य सीटों में लगभग **33 लाख** — यानी एक 'शरणार्थी मत' का चुनावी भार कई गुना अधिक (The Hindu)। JAAC कहती है कि इससे पाकिस्तान-आधारित दल क्षेत्र की सरकार को प्रभावित करते हैं।

संवैधानिक पक्ष: यह व्यवस्था 1974 के अंतरिम संविधान से आती है; 7 जून 2026 को PoK के सर्वोच्च न्यायालय ने सलाहकार राय में कहा कि ये सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं — समाप्ति के लिए **संवैधानिक संशोधन** आवश्यक, प्रशासनिक आदेश या सार्वजनिक दबाव से नहीं (BBC, 11 जून 2026)।

जून 2026: घटनाक्रम

मई का अंत: केंद्रीय मंत्री-दल और JAAC के बीच वार्ता विफल। **5 जून:** JAAC प्रतिबंधित; इंटरनेट-मोबाइल सेवाएँ 12 जून तक निलंबित; 'बाहरी' लोगों को क्षेत्र छोड़ने की सलाह; अर्ध-सैनिक बल तैनात (Amnesty International, 9 जून 2026)। **7 जून:** शीर्ष न्यायालय की संरक्षण-राय; JAAC केंद्रीय कार्यालय सील; 100 से अधिक गिरफ़्तारियाँ (Amnesty)। **8 जून:** रावलकोट में झड़पें — 11 मृत (6 प्रदर्शनकारी, 4 पुलिसकर्मी, 1 राहगीर — कमिश्नर के हवाले से Reuters/Al Jazeera)। **9 जून:** क्षेत्रव्यापी हड़ताल और मुज़फ़्फ़राबाद की ओर मार्च। रावलकोट झड़पों पर JAAC नेता शौकत नवाज़ मीर ने 'नरसंहार' का

आरोप लगाया; पुलिस आयुक्त ने कहा कि JAAC इसे 'नरसंहार' कहकर भ्रम फैला रही है (Al Jazeera, 8 जून 2026)। **मध्य-जून:** मृतकों की संख्या 20 से अधिक (Reuters, 19 जून 2026)।

मौतों के आंकड़े — तारीख़ के साथ पढ़ें

इस संघर्ष में मृत्यु-आंकड़ा तारीख़ और स्रोत के साथ बदलता है: 9 जून — 11 (Al Jazeera); 11 जून — 15 (BBC); 19 जून — 20 से अधिक (Reuters); 28 जुलाई — कम से कम 40, जिनमें 34 प्रदर्शनकारी और 6 पुलिस/अर्ध-सैनिक (Amnesty); अगस्त की शुरुआत में निवासियों और स्थानीय अनुमानों के अनुसार 50 से अधिक, प्रदर्शन-नेताओं का दावा 60 से अधिक नागरिक (Al Jazeera, 3 अगस्त 2026)। **सरकारी कुल आंकड़ा जारी नहीं हुआ**; सरकार ने केवल 7 पुलिस/अर्ध-सैनिक की मौत स्वीकारी (Al Jazeera, 24 सितंबर 2026)। कोई एक संख्या उद्धृत करना भ्रामक होगा।

बाद की स्थिति (अक्टूबर 2026 तक)

चुनाव तीन चरणों में: 27 जुलाई (मीरपुर), 2 अगस्त (मुज़फ़्फ़राबाद + 12 शरणार्थी सीटें), 10 अगस्त (पूंछ) — अशांति के कारण मूल तिथि बदलकर तीन-चरणीय कार्यक्रम बनाया गया; पूंछ डिवीज़न की 11 में से **7 सीटों** पर मतदान स्थगित रहा, 24 सितंबर तक नई तिथि नहीं (Al Jazeera)। परिणाम: PML-N ने 38 चुनित सीटों में 25 और 8 नामांकित में 6 जीतीं; PPP 12; मतदान **48%** (2021 में 61% था) (Al Jazeera, 24 सितंबर 2026)।

राष्ट्रपति चुनाव: 24 सितंबर 2026 को विधानसभा ने मतदान किया — पद 31 जनवरी 2026 से रिक्त था; PML-N के **नजीब नकी ख़ान** 32 मतों के साथ 25वें राष्ट्रपति चुने गए (PPP के चौधरी लतीफ़ अकबर को 13 मत) और उन्होंने शपथ ली (Geo News, 24 सितंबर 2026)।

इंटरनेट: ब्रॉडबैंड **13 सितंबर** को बहाल हुआ — 99 दिन बाद; मोबाइल डेटा कुछ भागों में तब भी प्रतिबंधित (Al Jazeera, 24 सितंबर 2026)। JAAC के प्रवक्ता शौकत नवाज़ मीर जून के अंत में गिरफ़्तार हुए; चार प्रवक्ताओं पर 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (~$36,000) के इनाम की घोषणा (Al Jazeera, 3 अगस्त 2026)।

भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

9 जून 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय PoK में 'नागरिक हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों' के लिए पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहराए; नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र की जाँच की माँग की (The Hindu, 13 जून 2026)। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारत के बयान को 'पूरी तरह' खारिज किया। 6 जून को लगभग 30 ब्रिटिश सांसदों ने अपने विदेश कार्यालय को पत्र लिखकर चिंता जताई (The Hindu)। Amnesty International ने प्रतिबंध को 'अनुपातहीन, गैर-कानूनी और संघ-स्वतंत्रता का उल्लंघन' कहा और स्वतंत्र जाँच की माँग की (9 जून 2026)।

नामों की राजनीति — PoK, AJK या 'Pakistan-administered'?

भारत इस क्षेत्र को **पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK)** कहता है; पाकिस्तान **'आज़ाद जम्मू-कश्मीर' (AJK)**; अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रायः 'Pakistan-administered Kashmir'। क्षेत्र अर्ध-स्वायत्त है — अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और न्यायपालिका, परंतु रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार पाकिस्तान के पास (1974 अंतरिम संविधान)। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के 'पक्ष में' शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं (The Hindu) — 'स्वायत्तता' की सीमा यहीं दिखती है।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा (PT): JAAC और उसका गठन-वर्ष (2023); 38-सूत्रीय माँग-पत्र; 12 आरक्षित सीटों का तर्क; AJK Anti-Terrorism Act 2014; तारीख़ें — 5 जून (प्रतिबंध), 8 जून (रावलकोट), 27 जुलाई/2 अगस्त/10 अगस्त (तीन चरण), 13 सितंबर (ब्रॉडबैंड बहाली); 53-सदस्यीय विधानसभा की संरचना; LoC (740 किमी)।

मुख्य परीक्षा GS-2: भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर प्रश्न; विवादित क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाएँ; प्रदर्शन-अधिकार बनाम आतंक-विरोधी कानून (Amnesty की आलोचना); इंटरनेट-बंदी और मानवाधिकार; क्षेत्रीय स्वायत्तता की औपचारिक बनाम वास्तविक सीमा।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

पाक-अधिकृत कश्मीर में 2026 के प्रदर्शन 'शरणार्थी सीटों' के प्रश्न से आगे बढ़कर शासन, प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता के गहरे संकट का सूचक हैं। समीक्षा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: जून 2026 की घटनाएँ और JAAC

मुख्य भाग में: तात्कालिक कारण: 12 आरक्षित सीटें और मत-भार असंतुलन; गहरे कारण: 2023 से आर्थिक शिकायतें (बिजली-बिल, गेहूँ), 38-सूत्रीय पत्र, संसाधन-आवंटन; राज्य-प्रतिक्रिया: प्रतिबंध, बल-प्रयोग, इंटरनेट-बंदी और उसकी सीमा-प्रश्न

निष्कर्ष में: संवैधानिक ढाँचे (1974) और स्थानीय जवाबदेही के बीच टकराव सुदीर्घ — भारत की कूटनीतिक टिप्पणी का संदर्भ।

स्रोत

- Al Jazeera: Deadly protests in Pakistan-administered Kashmir — What's going on?, 9 जून 2026
- BBC: At least 15 dead after deadly clashes in Pakistan-administered Kashmir, 11 जून 2026
- The Hindu Explained: Why are there protests in PoK?, 13 जून 2026
- Amnesty International: "Terrorism" designation marks dangerous escalation, 9 जून 2026
- Al Jazeera: Elections and protests — all you need to know, 3 अगस्त 2026
- Al Jazeera: At least 11 killed in Pakistan-administered Kashmir clashes before rally, 8 जून 2026
- Amnesty International: Authorities must lift communications blackout, 28 जुलाई 2026
- Geo News: PML-N's Dr Najeeb Naqi sworn in as 25th AJK president, 24 सितंबर 2026
- Al Jazeera: Pakistan-administered Kashmir votes for president amid unrest, 24 सितंबर 2026

यह भी पढ़ें: सिंधु जल विवाद: संधि की स्थिति, मध्यस्थता और भारत की आपत्ति।

याद रखें: प्रदर्शन की जड़ में 12 आरक्षित शरणार्थी सीटें हैं, पर विस्तार में शासन और स्वायत्तता का प्रश्न — 5 जून का प्रतिबंध, 8 जून की रावलकोट झड़पें, तीन-चरणीय चुनाव और 48% मतदान; और एक सबक़: मृत्यु-आंकड़ा हमेशा तारीख़ और स्रोत के साथ पढ़ें।